COUNCIL OF STATES

Wednesday, 11th February 1953

The Council met at, four of the clock in the afternoon, Mr. CHAIRMAN in the Chair.

PRESIDENT'S ADDRESS

SECRETARY: Sir, I beg to lay on the Table a copy of the President's Address to both Houses of Parliament assembled together today.

THE PRESIDENT (DR. RAJENDRA PRASAD):

The President addressing the Council:

1. The objects of the President's Address are to lay before the Council the state of the nation at the present time, and to make recommendations for the improvement of public affairs.

2. The President states that the government is committed to the principles of non-violence and peaceful coexistence. The government is also committed to the pursuit of economic and social development, and to the advancement of education and culture.

3. The President calls on the members of the Council to support the government in its efforts to achieve these objectives.

The President then concludes his address, urging the members of the Council to work together for the betterment of the nation.
[The President.]

वेदों की बातों में हस्ताक्षर करने की मेरी सरकार की लेखात्मक भी इस्कृ ति है कि नेतृत्व भारत पर जो विधेयक आ गई है उसको तो इस निमित्त माना है। जैसा कि सर्व-विशेषतः हमें चंदी बारे के सब वेदों के प्रति नेता और शासन की नीति बताने का प्रयास किया है। अंश: तथात: ये कोई भी जो इसमें सर्वोत्तम सहयोग नहीं होता है, इस चारणों और इसका अपने-अपने लेखों में और यह बात माने जा सकती है कि भारत राज्य में शासन का हार्मान है और यह कि यह उड़ जाना है जिसका परिणाम भविष्य की प्रवृति को मिलाता है। इसी नीति के अनुसार अन्य सरकारों में कुछ इस प्रकार प्रस्ताव पेश किये ब्यह इसके उस यह आया था जिसके कोरिया युद्ध के बारे में समझा हो जाता है।

इन प्रस्तावों के बाद भारत सरकार सम्बन्धित है, जिसे दुम्हार उन महान देशों में के कुछ इस विषय का नकाशा न कर सके जिनमें वह समकालीन समय में यह बुझ आता हैं, और उससे कोरिया की वजहों की गहरी गहराई और उसके पूरी रिपोर्ट हो नहीं हो जाता है। इसलिए यह सब कुछ संबंधीय संस्थाओं के लिए बहुत जरूरी बातें होंगी।

दूसरे राज्य और जापान के मार्ग के सब वेदों के प्रति मेरी की नीति भी बताती है। यहाँ वेदों में जिन लोकतंत्र अनुकूली तरीकों से हम आवाज है उन में समर्थन को सुनाईयों का विभाजितताओं के निर्देश निर्दिष्ट है। यदि लोकतंत्र की बात रहता है तो यह आयोजनक करता वितरण और समर्थन के प्रशिक्षण अन्तरराष्ट्रीय उद्देश्य में भी अपनाए आदेशहरू है।

५. मूल-विश्व व्यवस्था में संयुक्त राज्य की व्यवस्था सम्बन्धी साहित्य की बोलकर हर होगी और उन देशों में समर्थन की प्रमुखता किया जाएगा। संयुक्त राज्य के नेता में समायोजन प्रदर्शन के पूर्व करेंगे और तथा समर्थन की प्रवृति को बढ़ाने के लिए प्रायोजन करेंगे।

६. अंतों में, यह उल्लेख का आज भी सब से बड़ा कार्य बना हुआ है हालांकि पहले से जाना हो जाता है। मूल-विश्व व्यवस्था के निर्णय का दर्शाव करने के लिए संयुक्त राज्य के नेता में समायोजन प्रदर्शन के पूर्व करेंगे और समर्थन को अनुमंत करेंगे।

यह उल्लेख का आज भी सब से बड़ा कार्य बना हुआ है हालांकि पहले से जाना हो जाता है। मूल-विश्व व्यवस्था के निर्णय का दर्शाव करने के लिए संयुक्त राज्य के नेता में समायोजन प्रदर्शन के पूर्व करेंगे और समर्थन को अनुमंत करेंगे।
President's [11 FEB. 1953] Address

ब्यापक कद्रों को आप्तावेश कर लेना। ऐसे अनेक होते अब भी हैं जो इस समय की नहीं गुदारते कि आज की दृष्टियों में मुल्कीयौगिक प्रभाव और विनियम की महत्व नहीं खिया जा सकता और इसके बनाम रखने के किसी भी प्रयास का विरोध म्युक्षित हो जाएगा।

6. परिवर्तनीय और स्वायत्त्विक एवं इतिहास के हमारे पहली देशों के हमारे समय की बात जो होती से हमारे ध्वनिक और मंत्रालय में सहयोग की मात्रा बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में भी रुझान से कि हम भी समय की समस्या से बचने रहें हैं हमारे समयानुसार मूल्य बुद्धिमान है। यह नसीरुद्दीन बड़ा बड़ा हो गया है और हमीं जुगाद होगा है कि हमारे भाषाओं और रूपों के विचारों के बीच बहुत कुछ हुआ है। पाकिस्तान के प्राणपंथ के शुरुआती ज्ञान से हमारे देशों में जो उसके पुराने हुए वह नया भाषा हो गई है और इस रूप में क्या बदला कि जब वह जाँच कर रही है। यह विविधता है कि यह प्रयास जारी रखेंगे और ऐसे विकास जारी रखेंगे कि पुराने वंश और अन्य समय के समक्ष की अधिक प्राचीन समय के चल नहीं हैं। उन दिन का जन्म वड़ा कर लेंगे।

7. अमराबती बबक की शहरता से दोनों देशों के प्रतिनिधित्व बहुतों के पानी के प्रवास पर विशेष रूप से तय कर दिए रखे हैं। यह यथास्थित प्रेम पर ऐसा है कि विचार के अनुपाल होना बाधित नहीं होगा जो व्यक्ति के लिए बहुत उच्च व्यक्ति जिसमें वो दोनों देशों में होने वाले अनुभव प्रदर्शित हो। यह इस के बाद बड़ा समय आया है। यदि इसको ठीक तरह से बांधकर जिस भाषा और पाकिस्तान की ही बाहरी द्वीपों को यह नया पुनर्जीवन और मुक्तिकारी सिख होगा। यह दूमा भाषा की बात है कि ऐसे प्रश्न पर भी भाषा और सुधार की आवश्यकता के अवसर पर भी भाषा और सुधार की आवश्यकता के अवसर पर भी भाषा और सुधार की आवश्यकता के अवसर पर भी भाषा और सुधार की आवश्यकता के अवसर पर भी भाषा है।

8. भारत और पाकिस्तान के बीच में दूसरी सबसे प्राचीन समाज में भग्नार्क के राज की समस्या है। संयुक्तराष्ट्र के प्रतिनिधित्व के साथ हमारे प्रतिनिधित्व हमारे समय के लिए विचार कर रहे हैं। अब समय में सममता की उम्मीद समय को मुक्त माने जाएंगे कि पुराने वंश के समय की समस्या के अंतरराष्ट्रीय के साथ सममता समान की अधिक जानकारी हो। उन पर हमारा नहीं होगा यह पूर्व एवं इतनी और पाकिस्तान की भी हमें इसमें क्रान्ति को धारण करने का विचार है। यदि वह भाषा का भाषा कर दिया जाय तो हमारे समय में उन पर निर्भर करने की अर्थात भाषा होगा।

9. अन्य सभी ध्वनि में भग्नार्क और कल्याण राज्य में बहुत प्रकार के तर्क की है। उन ध्वनि के भाषा के साथ देशों में हमारे संविधान में विशेष उत्तरदायित्व है और भारत सरकार तथा भाषा और प्रकार के बीच है। उन ध्वनि के भाषा की हो जाएगा जो उन राज्य को भाषा से बांधते हैं और भी सुधार और भाषाकार कर दिया गया है। इस भाषा के यह भाषा पर अवनि हो जाएगा और अवनि कारक जल्द ही अपना में लाएगा।
7. [The President.] 

हुजूमबाबू जसू में नासमी अंग्रेज वासियों एक आदेश देने के लिए आयेगी। वह और अधिकारियों के प्रावधान करने हैं आयेगी विशेष रूप से इस समय में अधिकारियों के साथ-साथ सरकार के साथ बच्चे के लिए आयेगी।

10. भारतीय मानवों के प्रति उनके कार्य के विशेष भागों के लिए आयेगी। जब वे राहुल नामक वासियों के साथ बच्चे के लिए आयेगी।

वैश्विक और मानवीय कार्यों के साथ सहयोग है। 

12. श्री देश के नागरिक के लिए उनके कार्य के विशेष भागों के साथ सहयोग नहीं है। इस सब सहयोग का विशेष भाग है।
Presidents

13. Address

11 FEB. 1953

14. Address

11 FEB. 1953

15. Address

11 FEB. 1953

16. Address

11 FEB. 1953

17. Address

11 FEB. 1953

18. Address

11 FEB. 1953
11 President's [ COUNCIL ] Address 12

[The President.]

के लिये जीवों ने प्राय फिरे बा रहे हैं। नाम तोप पर समययुक्त के में इस वात के लिए प्रतिवेदन है कि बिकसित तरीकों से जित न माय बिस्तार लेकर भी सम्भवत है वादानां की पेंडार को बढ़ाया गया।

२८. जीवों के समार के लिये २२ प्रमुख जीवों के में १९५२-५३ में शुद्ध किये गये है। इसके अतिरिक्त यह विचार है कि अन्य समययुक्त योगदान के में एक प्रमुख व्यवसाय इकाई नियम की बार। आयोजक नियम की उन की पेंडार के लिये प्रत्यय करने के लिए बहुधे बिकसित की योगदान का पुनर्संचालन किया गया है। व्यय जीवन के कारण रहने के लिये एक संदर्भ की स्थापना की गई है। जीवापूर में मुख्यतः-विविधता बढ़ाने लगें।

२९. १९५२ में समार की कारणों ने एक वा अर्थी उद्योग जनरल संवैधानिक बनाया है। १९५२ में इसकी संपत्ति बढ़कर ३ लाख टन बाढ़ हो जायेंगी, ऐसी बात है। इसकी रंग १९५२ बाढ़ा विकल्प टन भारत ३३ लाख प्रति टन कर रही है।

२०. १९५२ में शुद्ध कारण के पेंडार जो न म अर्थ मात्र बढ़ी गई थी। वह मात्र ही नौ नामयुक्त रही और अन्य वाष्प के लिये और भी आयोजक पेंडार की सम्बन्ध है।

यथार्थ नियम नियंत्रण के कीमतों का कम होना शुद्ध की बात है तथा उसके कारण करने के लिए बढ़ाकर की बिक्री कम हो गई। और कारण व्यवसाय को विकास का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थायी ग्राम देश में लालों आयोजकों की जीवन का बढ़ना है।

में समार करने और अन्य कारकों ने बहुत महत्वपूर्ण मानता हैं यथार्थ बढ़ती लोगों की रोकथाम प्रदान करते हैं और इसीलिए भी व्यवस्था बेकारी को दूर करने के लिए अवश्य व्यवस्था पान है। अब भारतीय सांस्कृतिक और ग्रामीण उद्योगों में नौकरी की स्थापना की गई है। और सारा नौकरी करने के लिये अवश्य व्यवस्था की स्थापना की गई है। और सारा नौकरी करने के लिये व्यवस्था की स्थापना की गई है।

२१. अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के निर्माता के कारण चार व्यवसाय पर दुरा प्रभाव पड़ा है। याद रखिये के अपेक्षा और सबसे समय सुविधाओं विकास के लिये सरकार ने गठबंधन की है और उसका उत्तर है कि याद रखिये के हुए पहलु की जिस में बार के गत में गाँव में के भीतर बाली व्यवस्था भी सम्भवत होगी। जान करने के लिए एक प्रकार सम्भवत नियुक्त जान।

२२. संसार की नीतियों में पुनर्संचालन से वैदिक व्यवसाय और नवीनित नीतियों में कम हुआ है, और कुछ कम सीमा तक उसकी सामान्य भी कम हुई है। भूमि पुरावेश की नीति समीक्षा नित्य रही है नौकरी के अधिकार भी आयोजक भी कम हुआ है।

२३. भारत के उत्तर पूर्व और अधिक अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों के प्रति भी नीति सरकार विषय व्यवसाय देखी गई है और उनके विकास के लिये सहायता दी गई गई है। पिछले द्वि की समस्तों पर विचार करने के लिये एक आयोजन को नियुक्त की गई है। भारत में समाधान पानी की समस्याओं पर विचार करने के लिये एक समाधान पान आयोजन को नियुक्त की गई है।
President's Address [11 FEB. 1953]

24. This work must be done by the people of this country. We must work hard and diligently during the present working life. The President's Address is dated 11 February 1953.

25. The President's Address is in Hindustani. It is addressed to the people of the country. The President's Address is dated 11 February 1953.

26. The President's Address is in Hindi. It is addressed to the people of the country. The President's Address is dated 11 February 1953.

27. The President's Address is in English. It is addressed to the people of the country. The President's Address is dated 11 February 1953.

28. The President's Address is in Sanskrit. It is addressed to the people of the country. The President's Address is dated 11 February 1953.

29. The President's Address is in Urdu. It is addressed to the people of the country. The President's Address is dated 11 February 1953.

30. The President's Address is in French. It is addressed to the people of the country. The President's Address is dated 11 February 1953.
THE PRESIDENT (Dr. Rajendra Prasad): Members of Parliament, nine months ago, I welcomed you as members of the first Parliament of the Republic of India, elected under our Constitution. Since then, you have had to shoulder heavy burdens and to face difficult problems, both domestic and international. As we meet here today, we bring with us faith in our country's destiny and the assurance that our people are advancing, through their labours, towards the goal that we have set before us. These nine months have seen advances on many fronts, industrial and agricultural, and the finalisation of the Five Year Plan, which has mapped out the lines of our progress in the coming years. It is for us now to march along that path and to implement and fulfil the promise held out to our people. That is no easy task, for a multitude of old and new problems always tend to overwhelm us and our wishes often run faster than our capacity and resources.

2. At this moment, when we require all the wisdom and experience of our leaders, it is a misfortune that we have lost one of the most eminent and devoted of our elder statesmen. I learnt with deep sorrow of the death yesterday, in the early morning, of Shri N. Gopalaswami Ayyangar, who had filled, in the course of a full life, many high offices with rare distinction. To the end of his days, regardless of his health and the leisure he had so richly earned, he devoted his life to the service of his country and people. His colleagues in the Government and I relied on his ripe wisdom whenever any difficult problem confronted us. His death is a great loss to the country and to all of us.

3. While we labour in our own country to build up a new and prosperous India, bringing relief to the millions who have suffered so much in the past - from the curse of poverty, the problems of the rest of the world thrust them selves upon us and we cannot avoid them or isolate ourselves from them. My Government has no desire to interfere with other countries, but it has to face the responsibility which has inevitably come with independence to India. We have endeavoured, as is well known, to pursue a policy of peace and of friendship with all the countries of the world. Gradually, that policy has been understood and appreciated, even by those who may not always agree with it, and it is recognised that India stands for peace among the nations and will avoid taking any step which might encourage the tendency to war. In pursui
of this policy, my Government put forward certain proposals which they hoped might lead to a settlement of the Korean war. Those proposals met with a very large measure of support, but unfortunately some of the great countries most intimately concerned were unable to accept them. This war continues not only to the utter misery and ruin of the people of Korea, but also as a focus of danger for the rest of the world. Certain statements recently made, and the consequences that might flow from them in extending the war in Korea, have caused considerable apprehension in the minds of people all over the world. My Government has viewed these developments with grave concern. I trust that any tendency towards an extension of the war which has already brought disaster in its train, will be checked and the minds of nations and peoples will be turned towards a peaceful approach to these problems. My Government will continue to work to this end and will pursue a policy of friendship with all countries without any alignment with one group of nations against another. The democratic processes to which we are so firmly committed in our own country involve methods of peaceful approach to problems. If democracy is to survive, the same climate of peace and spirit of reconciliation has to be extended to the international sphere.

4. The General Assembly of the United Nations will meet again in the near future and will consider these grave problems, on which hangs the momentous issue of peace or war in the world. I earnestly hope that the great nations whose representatives will assemble there will address themselves to the promotion of a spirit of reconciliation and the fulfillment of the objectives embodied in the Charter of the United Nations.

5. In the continent of Africa, which continues to be the greatest sphere of colonialism today, events have taken a turn for the worse. In South Africa, the doctrine of racial domination is openly proclaimed and enforced by all the power of the State. The efforts made by the United Nations to deal with this problem have been ignored by the Government of the Union of South Africa. A movement against racial discrimination, which was remarkable for its peaceful and disciplined character, is sought to be crushed by legislation and governmental action, which are unique in their denial of democratic processes and the purpose which was proclaimed in the Charter of the United Nations. In East Africa there is racial conflict which, if not ended to the satisfaction of the people, is likely to extend and engulf vast areas of Africa. There are many people still who do not realize that racial domination and discrimination cannot be tolerated in the world today and any attempt to perpetuate them can only lead to disaster.

G. Our relations with our neighbour countries in Western and South-Eastern Asia continue to be close and friendly and there is an increasing measure of co-operation between us. Even in regard to Pakistan, with which unfortunately our relations have been strained, there has been a certain improvement. That improvement is not very great, but it is an indication which I welcome. Recent conferences between representatives of the two countries have been held in a friendly atmosphere and will, I hope, yield results. The upheaval caused by the introduction of the passport system between the two countries has subsided and many of the difficulties that were created by this system are being gradually removed. I trust that this effort will be continued and directed towards the removal of the basic problems that still confront the minorities in East Bengal.

7. The canal waters issue is being considered at a technical level jointly by representatives of the two countries, assisted by the International Bank. This issue is eminently one which ought to be considered objectively and dispassionately so that the maximum advantage can be derived by both countries from the waters that flow through them. A great proportion of these waters run waste to the sea. If they can be properly harnessed,
they will bring relief and prosperity to vast numbers of human beings in both India and Pakistan. It is unfortunate that an issue like this should be treated in a spirit and atmosphere of rivalry and hostility. I trust that the new approach will yield fruitful and happy results to both countries. This approach can also be applied to the settlement of the evacuee property problem which affects the fortunes of millions of people both in India and Pakistan.

8. Another vital issue between India and Pakistan has been the Jammu and Kashmir State. This matter is again being discussed by our representatives with the Representative of the United Nations. That issue, like others, has to be considered dispassionately, keeping always the welfare of the people of that State in view. It is not by war or threats of war that this, or any other outstanding problem between India and Pakistan, can be solved. My Government has declared repeatedly that it will not go to war unless it is attacked, and has invited a like declaration by Pakistan. If fear of war was eliminated, it would be much easier to consider all the issues that confront us today.

9. Internally, in the Jammu and Kashmir State, progress has been made in many ways. Our Constitution contains specific provisions about the relationship of India with the State, and by an agreement between the Government of India and the Jammu and Kashmir Government, the bonds that tie that State to India have been strengthened and made closer. A part of this agreement has been implemented and the remaining part should also come into operation soon. Unfortunately a misconceived agitation was started in Jammu which, though aiming at a closer union with India, is likely to have exactly the opposite effect. I trust that this misguided agitation will cease and the people of Jammu and Kashmir will co-operate for the progress and advancement of the State in the larger Union of India. Where there are legitimate grievances, they will undoubtedly be enquired into and every effort made to remove them.

10. The question of linguistic provinces has often agitated the people in various parts of the country. While language and culture are important considerations in the formation of States, it has to be remembered that the States are administrative units in the Union of India and that other considerations also have to be kept in mind. Above all, the unity of India and national security have always to be given the first priority. Financial and administrative aspects, as well as economic progress, are also important. Keeping all these factors in view, there is no reason why the question of the reorganisation of States should not be considered fully and dispassionately so as to meet the wishes of the people and help in their economic and cultural progress. I am glad that my Government has taken steps in the matter of the formation of a separate Andhra State: I hope that there will be no great delay in establishing this new State. Any such change as the establishment of a new State demands the fullest co-operation of all those concerned with it and I trust that this will be forthcoming.

11. The Planning Commission has completed the first part of its labours by finalising its report on the Five Year Plan. The other and the more difficult part, of implementing this plan, now faces the country and to that we must address ourselves. I am glad to find that this Plan and the fifty-five Community Projects that have been started in the country are evoking a considerable degree of enthusiasm among our people. In the course of a few months, hundreds of miles of roads have been built, tanks dug, school houses constructed and many other minor projects undertaken, almost entirely by the voluntary labour of our people. That is a sign of hope and promise, for it lies with our people ultimately what they make of their future.

12. The general economic situation in the country shows distinct signs of improvement, although there are still unfortunately areas where, owing to lack of rain, near-famine conditions
prevail. The State Governments are doing their utmost to give relief by utility works or otherwise in these areas. The problem, however, has to be tackled in a more basic way so as to avoid recurrence of famine conditions and a complete dependence upon the vagaries of the monsoon.

13. The Finance Commission, constituted towards the end of 1951 under the provisions of Article 280 of the Constitution, have submitted their report. The Commission’s recommendations have been accepted by my Government and necessary action will be taken for implementing them. The recommendations of the Commission will be laid on the Table of both Houses of Parliament in the current session.

14. There has been a steady improvement in the food situation and the closing stock for 1952 was 19 lakh tons, which is the highest on record so far. One of the factors in building up this stock was the wheat loan from the U.S.A. The prospects of foodgrains for 1952-53 are better than in the two preceding years. Owing mainly to the drought in parts of Bombay, Madras and Mysore, caused by an inadequate monsoon, foodgrains will have to be imported, but their quantity will be less than in the last two years. It is of the highest importance that we should gain self-sufficiency in food and I hope that this might be possible within the three remaining years of the Five Year Plan. For the first time we start this year with a considerable stock of food-grains. We should endeavour to build this up so that we can meet any contingency. Prices of foodgrains have shown a downward trend in recent months. Controls have been relaxed in many parts of India and there is greater freedom of movement. The Government, however, intend to retain control at strategic points so that no untoward results may affect prices or procurement.

15. The production of sugar during 1951-52 reached the record figure of 15 lakh tons and for the first time production exceeded internal requirements. This made it possible to relax control over the prices, movement and distribution of sugar, as well as on gur and khandsari. With the easing of the supply position of groundnut oil, controls of prices on hydrogenated oils have also been lifted, except those intended to ensure quality.

16. Very considerable progress has been made in cotton and jute production. In 1948-49 cotton production amounted to 17.7 lakh bales and jute 20.7 lakh bales. In 1951-52 cotton had increased to 31.3 lakh bales and jute to 46.8 lakh bales.

17. In order to add to the country’s food production, special attention is being paid to the construction of more than 2,000 tube-wells and for an accelerated programme of minor irrigation works. Crop competitions are becoming increasingly popular all over the country and have yielded very remarkable results. Large-scale experiments are being made to introduce what is called the Japanese method of rice cultivation which promises substantial results in increase of yield. A large mechanised farm has been set up in Jammu Province. Vigorous attempts are being made for the extensive application of fertilizers and other manure and for the use of improved seeds. The community centres are specially aiming at increasing the yield of foodgrains by various methods, including a rural extension service.

18. For the improvement of cattle 92 key farm centres were started in 1951-52. In addition it is proposed to provide one key village unit in each Community Project area. Sheep breeding schemes have been reorganised to provide for the production of fine wool. A Board for the preservation of wild life has been set up. At Jodhpur a Desert Afforestation Research Station is being established. This will undertake work for the reclamation of arid areas.

19. The Sindri Fertilizer Factory produced 180,000 tons of ammonium sulphate during 1952. This is expected
20. The production of cotton textiles, which amounted to 4,600 million yards during 1952, was highly satisfactory and the prospects for the next year are good. The lower prices of mill-made cloth, though welcome, led to a fall in the offtake of handloom cloth and the handloom industry, which provides livelihood to millions of people in the country, was faced with serious difficulties. My Government attaches great importance to this and other cottage industries both because vast numbers of people are employed in them and because they are the most effective method of removing unemployment. An All-India Khadi and Village Industries Board has been established and legislation undertaken to raise funds for technical development and research for village and cottage industries. In order to help the handloom industry, the production of dhoties by Tiill industry was curtailed to sixty per cent, of the 1951-52 production.

21. The tea industry was badly affected by the fall in international prices. The Government have taken measures to assist tea gardens to secure better credit facilities and propose to set up an expert committee to enquire into all aspects of the tea industry, including marketing. The price of tea is now showing some signs of improvement.

22. The readjustment of world prices affected foreign trade and exports fell in value and to a lesser extent, in quantity. The balance of payments position, however, continued to be satisfactory, as imports also declined.

23. My Government has been paying special attention to the tribal areas in the North-East and other parts of India and help is being given for their development. A Commission to consider the problems of backward classes has been appointed. A Press Commission has also been appointed to consider problems of the newspaper press in India.

24. The great multi-purpose river valley projects have made good progress and in some of them the operational phase will begin soon. Work on other projects has made steady progress.

25. Steps are being taken to improve the efficiency of the Hindustan Shipyard at Visakhapatnam and for the expansion of the Iron and Steel Industry. Production of coal, steel, cement, salt and fertilizers has reached higher levels than in the previous year.

26. Scientific research has made further progress by the establishment of new National Laboratories and Research Institutes. A Central Electro-Chemical Research Institute was opened at Karaikudi and the Central Leather Research Institute at Madras. The Building Research Institute at Roorkee will be opened soon. A factory for processing monazite sands has been set up at Alwaye in Travancore-Cochin and a Machine Tool Prototype factory was recently opened at Amber-nath in Bombay State. The Hindustan Aircraft Factory at Bangalore has produced, from its own designs, a number of trainer aircraft which are being used now. A defence factory near Jubbulpore is nearing completion.

27. My Government has decided to take under State control the existing air companies and to operate the scheduled air services. It is proposed to establish two State Corporations for this purpose, one for internal services and the other for external services.

28. Indian Railways are celebrating their centenary next month. This great State undertaking belonging to the community is continuing its progress and extending its operations.

29. The progress of a people and of a nation ultimately depends upon education. My Government views with much concern the present state of education in the country which suffers in many ways, both in quality and quantity, and too much attention is paid to the granting of diplomas and degrees and not to the real improvement of the individual in cultural, scientific and technical
matters and, above all, in the training for good citizenship. Basic education has been adopted as the model, but progress in this has thus far been unfortunately slow. Many schemes for the improvement of basic, secondary and social education, are under con-jation and a Commission on Secondary Education has been appointed.

30. An over-all view of the situation in India indicates allround general progress at an increasing pace. This is a matter for satisfaction. But the goal we have set before us is still far and requires greater and continuous effort and an increasing pace of change. We aim at a Welfare State in which all the people of this country are partners, sharing alike the benefits and the obligations. So long as there is poverty and unemployment, a section of the community derives no benefit from this partnership. It is, therefore, necessary for us to aim at full and productive employment.

31. A statement of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for the financial year 1953-54 will be laid before you. The Members of the House of the People will be required to consider and pass the demands for grants.

32. The House of the People will also be asked to vote supplementary grants to meet additional expenditure during the current financial year.

33. There are 24 Bills pending before you. Some of them have passed the Committee stage. A few of them, which are still under consideration by the Committees, will be brought before you with their recommendations during the course of this session.

34. Among the other legislative measures that it is intended to bring before you, the following may be especially mentioned: The Representation of the People (Amendment) Bill, the Bill on National Housing, the Air Services Corporation Bill, the Minimum Wages (Amendment) Bill, and the Indian Tariff (Amendment) Bill.

35. I earnestly trust, that wisdom and tolerance and the spirit of cooperative endeavour will guide you in your labours and will yield results for the good of the country and the people whom we are all privileged to serve.

EATH OF SHRI N. GOPALASWAMI AYYANGAR

THE PRIME MINISTER AND MINISTER FOR EXTERNAL AFFAIRS (SHRI JAWAHARLAL NEHRU): Mr. Chairman, before this House enters upon the labours of this session, may I refer to the passing away of a colleague of ours and the Leader of this House, Shri Gopalaswami Ayyangar? During the last session he was unable to attend to the business of this House because of his illness, and we all thought that it was, if I might call it so, a temporary illness which would pass, because we could not reconcile ourselves to the thought that he would not come back. We had come to rely upon him in so many matters that, as often happens, he became, in his own way, a kind of institution in Government to whom all turned for advice whenever any difficulty arose. And so we took this institution for granted. When un-towards events take place, they rather shake up the whole fabric of things. So it has been in this case, and though we grieve for him, in reality we grieve for ourselves, because he is not there for us to turn to. We may send our messages of sympathy to his family and others, and it is right that we should do so; but those who require most sympathy are ourselves.

Mr. Gopalaswami Ayyangar had a background and a record which, I suppose, is unusual in this House or among members of Government. Starting in the junior scale of Government service, he rose step by step till he seemed to be peculiarly fitted for any difficult problem or post of responsibility that might arise. In the course of his long and varied career he was, as the House might know, Prime Minister of the State of Jammu and Kashmir for five or six years. Those years were difficult years. Those years were war.